



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2005/वैशाख 12, 1927

No. 114]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2005/VAISAKHA 12, 1927

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2005

जांच शुरुआत (निर्णायक समीक्षा)

विषय :—सऊदी अरब, ईरान, जापान, यूएसए और फ्रांस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कास्टिक सोडा के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में निर्णायक समीक्षा की शुरुआत।

सं. 15/29/2004-डीजीएडी.—यतः 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिन्हें एतदपश्चात पाटनरोधी नियम कहा गया है) के अंतर्गत दिनांक 14 मई, 2001 की अधिसूचना सं० 56/1/99-डीजीएडी द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने सऊदी अरब, ईरान, जापान, यूएसए तथा फ्रांस (जिन्हें एतदपश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कास्टिक सोडा (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयात पर निश्चयात्मक शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए अपने अंतिम जांच परिणामों को अधिसूचित किया था।

और यतः दिनांक 26 जून, 2001 की सीमाशुल्क अधिसूचना द्वारा संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

2. विचाराधीन उत्पाद

मूल जांच और वर्तमान समीक्षा में शामिल उत्पाद सऊदी अरब, ईरान, जापान, यूएसए तथा फ्रांस के मूल का अथवा वहां से निर्यातित कास्टिक सोडा है जिसे आम तौर पर कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है। कास्टिक सोडा एक अकार्बनिक रसायन है और वह झागदार, अत्यधिक क्षारीय, गंधरहित होता है। कास्टिक सोडा का इस्तेमाल लुग्दी एवं कागज, अखबारी कागज, विस्कस यार्न, स्टेपल फाइबर, एल्यूमिनियम, सूत, वस्त्र, नहाने एवं कपड़े धोने के साबुनों, प्रक्षालक, रंजक सामग्री, औषध एवं भेषज के विनिर्माण, पेट्रोलियम शोधन इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। कास्टिक सोडा का उत्पादन दो स्वरूपों अर्थात् द्रव्य एवं ठोस में किया जाता है। वर्तमान जांच में कास्टिक सोडा के सभी स्वरूप शामिल हैं।

कास्टिक सोडा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत वर्गीकृत है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार श्रेणीकरण (सुमेलीकृत वस्तु विवरण एवं कोडिंग प्रणाली के आधार पर) के अनुसार इसे शीर्ष 2815.11 तथा 2815.12 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र पर किसी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

3. जांच शुरुआत

सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 और इसके अधीन निर्मित नियमों के अनुसार प्राधिकारी को लगाए गए पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की जरूरत की समय-समय पर समीक्षा करनी अपेक्षित होती है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 की धारा 9क(5) के प्रावधान के तहत, इस चरण पर सिफारिश किए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा करना उचित होगा। सऊदी अरब, ईरान, जापान, यूएसए तथा फ्रांस के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तुओं पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की आवश्यकता की पुष्टि करते हुए मै0 अल्कली मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, दिल्ली ने याचिका दायर की है तथा यह अनुरोध किया है कि ऊपर उल्लिखित अधिसूचनाओं के अंतर्गत संबद्ध वस्तु पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को 5 वर्ष की अवधि तक आगे बढ़ाया जाए।

4. शामिल देश

वर्तमान जांच में शामिल देश सऊदी अरब, ईरान, जापान, यूएसए तथा फ्रांस हैं।

5. समीक्षा के लिए आधार

याचिकाकर्ता ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका, क्लोर अल्कली में निहित सूचना के आधार पर संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का दावा किया है। क्लोर अल्कली में संबद्ध देशों के घरेलू बाजारों में कास्टिक सोडा की कीमतों के बारे में सूचना उपलब्ध होती है। प्राधिकारी ने प्रथम दृष्ट्या जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ, याचिकाकर्ताओं द्वारा गौण स्रोतों से उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

याचिकाकर्ता द्वारा डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता तथा गौण स्रोतों से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का दावा किया गया है। निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए, समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, निर्यात के देश में अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन हैंडलिंग तथा पत्तन प्रभार, कमीशन इत्यादि के संबंध में कीमत समायोजनों का दावा किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार निर्यात कीमत, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के लिए दावा किए गए समायोजनों का पर्याप्त साक्ष्य है इसलिए प्राधिकारी ने जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ इन पर विचार किया है।

अनुरोध इस पृष्ठभूमि पर आधारित है कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति का परिणाम पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति के रूप में होने की संभावना है।

आवेदक ने आरोप लगाया है कि यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया गया तो क्षतिकारी पाटन के पुनः प्रारंभ होने की संभावना है, चीन जनवादी गणराज्य में अप्रयुक्त क्षमता और वृहत् भंडार की उपस्थिति के कारण चालू आयातों में वृद्धि हो सकती है। इसके अतिरिक्त, आवेदक का आरोप है कि क्षति की सम्पत्ति मुख्य रूप से पाटनरोधी शुल्क की उपस्थिति के कारण है और यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो चीन जनवादी गणराज्य से पाटित कीमतों पर अत्यधिक आयातों की पुनरावृत्ति से घरेलू उद्योग को पुनः क्षति होने की संभावना है।

6. प्रक्रिया

दिनांक 14.05.2001 की सं0 56/1/99-डीजीएडी द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणाम तथा 26.06.2001 की अधिसूचना द्वारा लागू अंतिम शुल्क की समीक्षा करने का निर्णय लेने के पश्चात, प्राधिकारी सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 तथा पाटनरोधी नियमों के अनुसार सउदी अरब, ईरान, जापान, अमरीका तथा फ्रांस के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित कौस्टिक सोडा के आयातों के बारे में यह समीक्षा करने के लिए जांच शुरू करते हैं कि क्या पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा फिर से होने की संभावना है।

इस समीक्षा में 14.05.2001 की अधिसूचना सं0 56/1/99-डीजीएडी के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। मूल जांच में भी मै0 एल्कली विनिर्माणा एसोसिएशन ऑफ इण्डिया, दिल्ली ने घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व किया है। प्राधिकारी नियमावली के अनुसार आवेदनकर्ता, जो भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन के बड़े भाग का उत्पादन करते हैं, को घरेलू उद्योग का प्रतिनिधि मानने का प्रस्ताव करते हैं।

7. जांच की अवधि

वर्तमान समीक्षा के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2003 से 30 सितम्बर, 2004 (18 महीने) तक की है। तथापि, क्षति विश्लेषण में वर्ष 2000-01 से 2003-सितम्बर 2004 तक की अवधि शामिल होगी।

8 सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देशों के निर्यातकों और भारत में उनके दूतावासों/उच्चायोगों/प्रतिनिधियों के माध्यम से उनकी सरकारों, ज्ञात संबद्ध आयातकों और उपयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को संबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से प्रस्तुत करने और अपने विचारों से निम्नलिखित को अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है।

निर्दिष्ट प्राधिकारी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी), कमरा सं०-240, उद्योग भवन, नई दिल्ली- 110011

अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से जांच से संबंधित अनुरोध कर सकती है।

9. समय सीमा

वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना तथा सुनवाई के लिए कोई अनुरोध प्राधिकारी को उपर्युक्त पते पर इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर पहुँच जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण हो तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं।

10. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं। यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या जांच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

क्रिस्टी फेर्नान्डेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd May, 2005

Initiation Notification (Sunset Review)

Subject : Initiation of Sunset Review regarding anti-dumping duty imposed on imports of Caustic Soda originating in or exported from Saudi Arabia, Iran, Japan, USA and France.

No. 15/29/2004-DGAD.—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (herein after referred to as AD Rules), vide Notification Number 56/1/99-DGAD dated 14th May 2001. The Designated Authority (herein after referred to as the Authority) notified its final findings recommending definitive antidumping duty on import of Caustic Soda (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from Saudi Arabia, Iran, Japan, USA and France (hereinafter referred to as subject countries).

And Whereas definitive antidumping duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification dated 26th June, 2001.

2. Product Under Consideration

The product involved in the original investigation and this current review is Caustic Soda, commonly known as Caustic Soda originating in or exported from Saudi Arabia, Iran Japan, USA and France .Caustic Soda is an inorganic chemical and is soapy , strongly alkaline odourless chemical. Caustic Soda finds application in various fields like manufacture of pulp and paper, newsprint, viscose yarn, staple fibre, aluminium, cotton, textiles, toilet and laundry soaps, detergent, dyestuffs, drugs and pharmaceuticals, petroleum refining, etc.. Caustic soda is produced in two forms, i.e. Lye and solids. Present investigation covers all forms of caustic soda.

1356 GI/05-2

Caustic Soda is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975. It is further classified as per International Trade Classification [based on Harmonized Commodity Description and Coding System] under the heading 2815.11 and 2815.12. The classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

3. Initiation

The Customs Tariff (Amendment) Act 1995 and the AD Rules made there under require the Authority to review from time to time the need for continuance of anti-dumping duty. The Designated Authority considers that the sunset review of the anti dumping duty recommended would be appropriate at this stage under the provision of section 9A (5) of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 as amended. M/s. Alkali Manufacturers Association of India, Delhi, have filed an application substantiating the need for sunset review of the anti-dumping duty imposed on the subject goods originating in or exported from Saudi Arabia, Iran, Japan, USA and France and have requested for continuation of the anti-dumping duty imposed on subject goods under the above mentioned notifications for a further period of 5 years.

4. Countries Involved:

The countries involved in the present investigations are Saudi Arabia, Iran, Japan, USA and France .

5. Grounds for Review

The petitioner has claimed normal value of subject goods in subject countries on the basis of information from leading International journal i.e., Chlor Alkali. Chlor Alkali reports the prices of Caustic Soda in the domestic market in subject countries. The authority has prima facie, considered the normal value of the subject goods in subject countries on the basis of information made available by the petitioner from the secondary sources for the purpose of initiation. The export price has been claimed on the basis of data provided by the applicant from DGCI&S, Kolkata and secondary sources. Price adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation in the country of exports, port handling and port charges, commissions etc. to arrive at the net export price. There is sufficient evidence of export price, the adjustments claimed for the subject goods from the subject country, as made available by the applicant, the authority has considered it for the purpose of initiation.

The request is based on the grounds that the expiry of anti-dumping duty would be likely to result in a continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

The applicant has further alleged that likelihood of further injurious dumping if the anti-dumping duty be allowed to lapse, the current imports may likely to increase due to existence of unused capacity and the large reserves in the China PR. In addition the applicant alleges that the removal of injury is mainly due to the existence of anti-dumping duty and any recurrence of substantial imports at dumped prices from China PR would likely to lead to a recurrence of injury of the domestic industry if anti-dumping duty be allowed to lapse.

6. **Procedure:**

Having decided to review the final findings notified vide No. 56/1/99-DGAD dated 14/5/2001 and final duty imposed by Notification dated 26/6/2001, the Authority hereby initiates investigations to review whether cessation of antidumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury on imports of Caustic Soda originating in or exported from Saudi Arabia, Iran, Japan, USA and France, in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and AD Rules.

The review covers all aspects of Notification No.56/1/99-DGAD dated 14/5/2001. M/s. Alkali Manufacturers Association of India, Delhi have represented on behalf of the domestic industry in the original investigations also. The Authority proposes to consider the applicant, who constitutes the major proportion of the production of the subject goods in India, as domestic industry in accordance with the Rules supra.

7. **Period of Investigation:**

The period of investigation for the purpose of the present review is 1st April 2003 to 30th September 2004 (18 months). However, injury analysis shall cover the years from 2000-01 to 2003 - September 2004.

8. **Submission of Information:**

The exporters in subject countries, their government through their Embassies/High Commissions in India/representatives, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit

relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the:

**The Designated Authority,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties, (DGAD),
Room No. 240, Udyog Bhavan,
New Delhi-110011**

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

9. Time Limit:

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

10. Inspection of Public File:

In terms of Rules 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

CHRISTY FERNANDEZ, Designated Authority